न्यूज डायरी

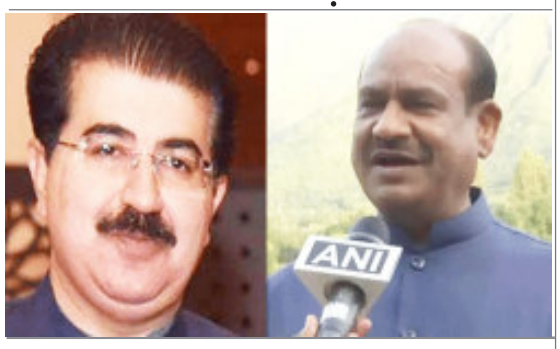

पाकिस्तानी सीनेट के जहरीले मुखिया ने ओम बिड़ला को दिया झटका

एजेंसी (वेब वार्ता न्यूज) इस्लामाबाद। पाकिस्तानी संसद के ऊपरी सदन सीनेट के विवादित मुखिया सादिक सांजरानी ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला के भारत आने के न्योते को ठुकरा दिया है। सादिक सांजरानी ने कहा कि वह भारत के अनुच्छेद 370 को खत्म करने फैसले के विरोध में नई दिल्ली की यात्रा पर नहीं जा रहे हैं। सादिक ने पीएम मोदी की सरकार के खिलाफ कश्मीर को लेकर कई जहरीले बयान भी दिए। इससे पहले लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने संसद की लोक लेखा समिति के 100 साल पूरा होने के मौके पर चार–पांच दिसंबर को दिल्ली में होने जा रहे विशेष कार्यक्रम में सादिक को आमंत्रित किया था। इस कार्यक्रम में पीएम मोदी को भाषण भी देना है। ओम बिड़ला के पाकिस्तानी सीनेट अध्यक्ष को न्योता देने से भारत में विवाद पैदा हो गया था।

सऊदी अरब ने लाखों भारतीयों को दी बड़ी राहत

एजेंसी (वेब वार्ता न्यूज) रियाद। सऊदी अरब ने लाखों की तादाद में नौकरी कर रहे भारत, पाकिस्तान समेत 6 देशों के नागरिकों को बड़ी राहत दी है। इन देशों के लोगों को अब किसी तीसरे देश में 14 दिनों तक क्वारंटाइन में नहीं बिताना होगा। यह नया आदेश इस साल 1 दिसंबर से लागू हो जाएगा। पिछले साल फरवरी महीने में वैश्विक स्तर पर कोरोना के प्रसार के बाद यात्रियों के सीधे प्रवेश पर रोक लगा दिया गया था। सऊदी प्रेस एजेंसी ने गृह मंत्रालय के सूत्रों के हवाले से यह बैन हटने की जानकारी दी। सऊदी अरब ने ब्राजील, वियतनाम, इंडोनेशिया, मिस्र के लोगों को भी अब सीधे प्रवेश की अनुमति दे दी है। हालांकि इन सभी देशों से आने वाले नागरिकों को 5 दिन संस्थागत क्वारंटीन रहना होगा। हालांकि यह उनके वैक्सीन लगवाने की स्थिति पर निर्भर करेगा। सऊदी अरब का स्वास्थ्य मंत्रालय लगातार सभी नियमों और कदमों की समीक्षा करता रहेगा। गृह मंत्रालय ने कहा कि जो लोग सऊदी अरब आना चाहते हैं, उन्हें सभी तरह के स्वास्थ्य उपायों को मानना होगा।

अपने क्रूर रवैये पर वापस आएगा तालिबानः एक्सपर्ट

एजेंसी (वेब वार्ता न्यूज) काबुल। अफगानिस्तान पर तालिबान ने कब्जा कर अपनी सरकार का तो गठन कर लिया है लेकिन अब वो यहां पर लंबे समय तक स्थिरता देने के लिए संघर्ष कर रहा है। ये कहना है कि फ्रेंच नेशनल सेंटर फार साइंटिफिक रिसर्च के शोधकर्ता एडम बैक्जो का। उन्होंने पालिसी रिसर्च ग्रुप स्ट्रेटेजिक इंसाइट में लिखा है कि तालिबान बेहद महीन सी लकीर के ऊपर चल रहा है। इसमें एक तरफ नैतिकता है तो दूसरी तरफ वो है जो वो करना चाहता है। इस लिहाज से वो ये भी फैसला नहीं कर पा रहा है कि अपनी सरकार को स्थिरता देने के लिए वो किस तरफ जाए। इसको लेकर वो पूरी तरह से कंफ्यूज हो रहा है। ब्यूरोक्रेसी की समझ और नियम और कानूनों की जानकारी जिसमें मानवाधिकार भी शामिल है, तालिबान को नहीं है।

रोहिंग्या शरणार्थियों का ठिकाना होगा बंगाल की खाड़ी में बसा ये द्वीप

एजेंसी (वेब वार्ता न्यूज) ढाका। बांग्लादेश ने सैकड़ों रोहिंग्या शरणार्थियों को बंगाल की खाड़ी में स्थित एक द्वीप पर भेजना शुरू किया। मानवाधिकार संगठनों ने समुद्र में डूब के खतरे का सामना कर रहे द्वीप पर मौजूद परिस्थितियों को लेकर चिंता प्रकट की है। पड़ोसी देश म्यांमार में अगस्त 2017 में हिंसा और उत्पीड़न शुरू होने के बाद रोहिंग्या मुस्लिम समुदाय के लाखों लोग पलायन कर गए थे। इनमें से 11 लाख रोहिंग्या समुदाय के नागरिकों ने बांग्लादेश में शरण लिया। रोहिंग्या को द्वीप पर भेजे जाने के कार्य की निगरानी कर रहे एक वरिष्ठ अधिकारी मुहम्मद शमशाद दौजा ने कहा कि नौसेना का एक जहाज 379 शरणार्थियों को चट्टोग्राम सिटी से भशान चर द्वीप ले जाएगा। यह द्वीप देश के दक्षिण पूर्वी तट पर स्थित है। वे लोग स्वेच्छा से जा रहे हैं। कुल 1500 रोहिंग्या अगले कुछ हफ्तों में चरणबद्ध तरीके से द्वीप पर भेजे जाएंगे।

चीन के साथ रिश्ता जोड़ना अब सोलोमन द्वीप के लिए पड़ रहा भारी

आरोप

सोलोमन द्वीप के प्रधानमंत्री ने प्रदर्शनों के लिए विदेशी हस्तक्षेप को जिम्मेदार ठहराया

एजेंसी (वेब वार्ता न्यूज)

कैनबरा। ताइवान के साथ नाता तोड़कर चीन के साथ रिश्ता जोड़ना अब सोलोमन द्वीप के लिए भारी पड़ रहा है। सोलोमन द्वीप के लोग ड्रैगन के साथ इस दोस्ती को पचा नहीं पा रहे हैं और ताजा हिंसा के पीछे इसे भी एक बड़ा कारण माना जा रहा है। उधर, सोलोमन द्वीप के प्रधानमंत्री मनासेह सोगावरे ने हाल के दिनों में राजधानी होनियारा में हुए सरकार विरोधी प्रदर्शनों, आगजनी और लूटपाट के लिए शुक्रवार को विदेशी हस्तक्षेप को जिम्मेदार ठहराया। दरअसल, सोलोमन द्वीप एक संप्रभु देश है जिसमें 6 प्रमुख द्वीप और ओशिनिया के 900 से अधिक छोटे द्वीप आते हैं। सोगावरे ने 2019 में कई लोगों, खासतौर से सोलोमन द्वीप के सबसे घनी आबादी वाले प्रांत मलाइता के नेताओं को उस समय नाराज कर दिया था जब उन्होंने ताइवान के साथ देश के राजनयिक संबंध खत्म कर दिए।

देश के रक्षा मंत्री पीटर डटन ने कहा कि ऑस्ट्रेलियाई पुलिस और राजनयिकों को लेकर आने वाला एक विमान गुरुवार को होनियारा में पहुंचा, जहां वे दूसरे दिन सरकार विरोधी हिंसक प्रदर्शनों के बाद शांति व्यवस्था कायम करने के प्रयासों में स्थानीय पुलिस की मदद करेंगे।

मैं किसी के भी आगे झुकने वाला नहीं हूं, हम अपनी बात पर कायम

सोगारवे ने कहा कि वह चीन से राजनयिक संबंध स्थापित करने के अपने सरकार के फैसले पर अडिग हैं और उन्होंने इसे हिंसा का 'एकमात्र मुद्दा' बताया। उन्होंने कहा, 'मैं किसी के भी आगे झुकने वाला नहीं हूं। हम अपनी बात पर कायम है, सरकार भी अपनी बात पर काम है और हम लोकतंत्र की रक्षा करेंगे।' सोगारवे के आलोचकों ने अशांति के लिए सरकारी सेवाओं की कमी और भ्रष्टाचार की शिकायतों को भी जिम्मेदार बताया।

ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री मारिस पायने ने इस पर बात पर सहमति नहीं जतायी कि अशांति के लिए दूसरे देश जिम्मेदार हैं। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने शांति व्यवस्था बहाल करने और अहम प्रतिष्ठानों की रक्षा करने में स्थानीय पुलिस की मदद के वास्ते सैनिकों, पुलिस और राजनयिकों को भेजने की गुरुवार को प्रतिबद्धता जतायी। कुछ पर्यवेक्षकों की दलील है कि शांति व्यवस्था बहाल करने को लेकर चीन के सुरक्षा बलों को आने से रोकने के लिए ऑस्ट्रेलिया ने तत्काल हस्तक्षेप किया है, लेकिन मॉरिसन ने कहा कि सोगारवे ने मदद के लिए कहा है क्योंकि वह ऑस्ट्रेलिया पर भरोसा करते हैं।

चीन ने चीनी नागरिकों पर हाल में हुए हमलों को लेकर गंभीर चिंता जतायीः इस बीच, चीन ने कुछ चीनी नागरिकों और संस्थानों पर हाल में हुए हमलों को लेकर गंभीर चिंता जतायी है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजिआन ने गुरुवार को कहा, 'हम मानते हैं कि प्रधानमंत्री सोगारवे के नेतृत्व में सोलोमन द्वीप सरकार जल्द से जल्द सामाजिक व्यवस्था एवं स्थिरता बहाल कर सकती है।'

मुंबई में कसाब के आतंकी हमलों को यादकर बोला इजरायल

एजेंसी (वेब वार्ता न्यूज)

यरूशलम। साल 2008 में आज ही के दिन मुंबई में हुए आतंकी हमलों को यादकर इजरायल ने कहा है कि हम पीड़ितों को हरगिज नहीं भूलेंगे। मुंबई में इजरायली वाणिज्य दूतावास के महावाणिज्य दूत कोब्बी शोशानी ने ट्वीट कर इस खौफनाक आतंकी हमले को याद किया। उन्होंने कहा कि हम मुंबई हमलों के पीड़ितों को कभी नहीं भूलेंगे। उधर, इजरायल में भी भारतीय लोगों ने मुंबई हमले के साजिशकर्ताओं को जल्द से जल्द सजा देने की मांग की है।

इजरायल में भारतीयों ने लश्कर–ए–तैयबा के इस हमले मारे गए लोगों को याद किया और अपराध के 'मास्टरमाइंड' को सजा देकर जल्द न्याय देने की मांग की। उन्होंने इन हमलों की 13वीं बरसी की पूर्व संध्या पर आतंकवाद की समस्या से निपटने के लिए समन्वित प्रयास करने की मांग की। इजराइल में सभी प्रमुख संस्थानों में भारतीय छात्र, भारतीय यहूदी समुदाय के सदस्य और इजराइल में रह रहे तथा काम कर रहे भारतीयों ने 26/11 हमलों की बरसी की पूर्व संध्या पर गुरुवार को देशभर में कई कार्यक्रम आयोजित किए और आतंकी हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी। इन हमलों में मारे गए लोगों में 6 यहूदी भी शामिल हैं।

हरी आंखों वाली शरबत गुल को इटली में मिली पनाह

एजेंसी (वेब वार्ता न्यूज) काबुल। अपनी हरी आंखों से पूरी दुनिया को दीवाना बनाने वाली अफगान लड़की तालिबान की क्रूरता से बड़ी राहत मिल गई है। साल 1985 में नैशनल जियोग्राफिक के कवर पेज पर छपने वाली शरबत गुला को इटली ने सुरक्षित पनाह दे दी है। शरबत तालिबानी आतंकियों से बचने के लिए छिपकर अफगानिस्तान से निकल गई थीं। पाकिस्तान के एक शरणार्थी शिविर में रह रहीं शरबत मात्र 12 साल की उम्र में उस समय अफगान युद्ध का चेहरा बन गई थीं, जब उनकी हरी आंखों वाली तस्वीर मैगजीन में छपी थी। इसके कुछ साल बाद शरबत को पाकिस्तान में वर्ष 2016 में अरेस्ट कर लिया गया था।

अमेरिका ने कूटनीति के मोर्चे पर चीन को दी पटखनी

एजेंसी (वेब वार्ता न्यूज)

नई दिल्ली। चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग के साथ अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन की वर्चुअल बैठक के ठीक बाद बाइडन प्रशासन के इस कदम से चीन को मिर्ची जरूर लगी होगी। दोनों नेताओं की बैठक के बाद राष्ट्रपति बाइडन ने डेमोक्रेसी पर वर्चुअल समिट बुलाई थी। बाइडन के इस आमंत्रण पर करीब 110 देशों ने हिस्सा लिया। खास बात यह है कि इसमें चीन को आमंत्रित नहीं किया गया है, जबकि ताइवान को बुलाया गया। बाइडन की डेमोक्रेसी कार्ड के क्या कूटनीतिक मायने हैं। इस कार्ड के जरिए अमेरिका ने चीन को क्घ्या बड़ा

दुनिया के अन्य मुल्कों से अलग–थलग करना मकसद

संदेश दिया। भारत के लिए यह क्यों खास है। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडन का लोकतंत्र पर महासम्मेलन के बड़े मायने हैं।

दरअसल, चिनफिंग और बाइडन के बीच हुई वर्चुअल बैठक बेनतीजा रहने के बाद बाइडन प्रशासन ने शायद यह तय कर लिया है कि चीन को कूटनीतिक मोर्चे पर शिकस्त करना है। उसे दुनिया के अन्य मुल्कों से अलग–थलग करना है। लोकतंत्र पर चीन के बहिष्कार को इसी कड़ी के रूप में देखना चाहिए। आने वाले समय में बाइडन प्रशासन की नीति में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। राष्ट्रपति बाइडन चीन से सामरिक या रणनीतिक संघर्ष के बजाए कूटनीतिक दांव से चित करने की रणनीति बना सकते हैं।

शीत युद्ध के दौरान पूर्व सोवियत संघ और अमेरिका के बीच सामरिक और वैचारिक संघर्ष एक साथ चलते थे। नाटो संगठन का उदय भी इसी रूप में देखा जाना चाहिए। नाटो एक व्यवस्था, एक विचार, एक हित वाले देशों का एक शक्तिशाली संगठन है। यह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पूर्व सोवियत संघ के खिलाफ था। इसका मकसद पूर्व सोवियत संघ को हर मोर्चे पर घेरना था। पूर्व सोवियत संघ के पतन के बाद नाटो की भूमिका में बदलाव आया है। चीन की महाशक्ति बनने की होड़ में बाइडन प्रशासन एक बार फिर इस नीति पर लौट आया है।

दुनिया से 10 साल ज्यादा हो गई ताइवान के लोगों की उम्र

एजेंसी (वेब वार्ता न्यूज) ताइपे। ताइवान के लोग पहले की तुलना में अधिक समय तक जी रहे हैं, इसलिए नहीं कि उन्होंने आदर्श आहार की खोज की है। वे सामान्य तौर पर अपने जीवन से अधिक खुश और संतुष्ट भी हैं। अपने शहरों को बुजुर्गों के अनुकूल बनाने की पहल के तहत ताइवान वृद्ध लोगों को बेहतर हालात प्रदान करने के लिए सहयोगात्मक और सामाजिक वातावरण प्रदान करता है। ताइवान की राजधानी ताइपे में डब्ल्यूएचओ के प्रारूप के अनुसार बुजुर्गों के लिए बेहतर ढांचा तैयार करने पर 2012 से काम हो रहा है। यह ढांचा सामाजिक और बेहतर बुनियादी ढांचा वाले वातावरण को कवर करने वाले आठ परस्पर जुड़ाव के विषय का प्रस्ताव करता है। डब्ल्यूएचओ ने बाहरी स्थान और इमारतों, परिवहन, आवास, सामाजिक भागीदारी, सम्मान और सामाजिक समावेश, नागरिक भागीदारी और रोजगार, संचार तथा सूचना प्रमुख के क्षेत्र में बुजुर्गों के लिए शहरों को उपयुक्त बनाने पर ध्यान केंद्रित करने के वास्ते सामुदायिक सहायता और स्वास्थ्य सेवाओं की पहचान की है। ऐसा लगता है कि यह काम कर रहा है।